

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

नम्बर 236/2015

दायर दिनांक-12-10-2015

विजय सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

- वादी

बनाम

- अजय सिंह पुत्र जयसिंह
- गेदकंवर बेवा जयसिंह
- भवानीराज पुत्र उम्मेद सिंह
- भवानी राज पुत्र उम्मेद सिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० सौभाग्य सिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० सौभाग्य सिंह
8. हिम्मत सिंह पुत्र स्व० सौभाग्य सिंह
9. संग्राम सिंह पुत्र कल्याण सिंह
10. जितेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
11. विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
12. प्रभू सिंह पुत्र नारायण सिंह
13. श्योदान सिंह उर्फ सुजान सिंह पुत्र नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
14. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

कील वादी :- श्री सज्जन कुमार चाहर
कील प्रति. नं. :- श्री जयपाल सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ व
रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
-:: निर्णय ::-

दिनांक-25-07-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- राजस्व ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 1644 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा नया खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये थे इसके नये खसरा नम्बर 2722 कुल रकबा 0.90 हैक्टर है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की पैतृक कब्जे काशत की भूमि है जो कि वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावगी।

वाद-पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 1644 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा नया खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये गये थे। इसके नये खसरा नम्बर 2722 कुल रकबा 0.90 हैक्टर बने जो कि अब गैर मुमकीन नदी है। इसमें वादी व प्रतिवादीगण के दादा जोध सिंह थे, जो कि भूमि खसरा नम्बर पुराने नम्बर 1644 कृषि भूमि थी जिसके खातेदार आस कंवर, उम्मेद सिंह, जयसिंह, नारायणसिंह, सुमेर सिंह, किशोर सिंह, शिवसिंह आदि थे। पुराने खसरा नम्बर 1644 कृषि भूमि थी और उससे मिलन क्षेत्रफल के मुताबिक भू-प्रबन्ध कार्य भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा नये खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये गये थे। इस खसरा नम्बर 5192/3361 के कायम होने के बाद में अलग से नया राजस्व ग्राम बनने पुनः नम्बर बदले जाकर हाल खसरा नम्बर 2722 बनाये गये है। इस प्रकार कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर से बनने वाले नये खसरा नम्बर की भूमि की किस्म नही बदली जा सकती है, परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना अधिकार के और बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत कृषि भूमि से

ए. सी. ई. (प्र. डे.)
नवलगढ़

ने वाड़े नये खसरा नम्बरान को गैरमुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित किया है, जब कि कृषि भूमि से बनने
ने नये खसरा नम्बरान को गैरमुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परन्तु इसके
भी भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकारों के गलत रूप से गैर मुमकीन नदी के
में परिवर्तित किया है। भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भू-प्रबन्ध कार्य के दौरान
पुराने रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। केवल मात्र पुराने रिकार्ड की पुनरावृत्ति करने
अधिकार था, और किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में पुराने रिकार्ड में कोई भी परिवर्तन या
बदल करने का भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को दौरान भू-प्रबन्ध कार्य कोई कानूनी
अधिकार प्राप्त नहीं थे, परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के बिना किसी आधार के कृषि को
गैरमुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित किया है, जो कि कतई गलत व बिना अधिकार के किया गया है।

गैर मुमकीन नदी के रिकार्ड में भी भूमि पुराने खसरा नम्बर 1644 की भूमि दर्ज नहीं थी। मिलान
क्षेत्रफल भूमि खसरा नम्बर पुराने 1644 की भूमि दर्ज नहीं थी। मिलान क्षेत्रफल भूमिखसरा नम्बर 1644 व
खातेदार की भूमि पुराने खसरा नम्बर 1644 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से सम्वत् 2020 जिसके पुराने
खसरा नम्बर 2063 थे जो जोध सिंह व ठाकुर फतेह सिंह के नाम थी उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर
सम्वत् 2021 में बदलकर 1644 हो गये व भूमि 2 बिघा 8 बिस्वा थी जो आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5
किशन सिंह, मूल सिंह, उम्मेद सिंह व जय सिंह पिता जोध सिंह कौम राजपूत हिस्सा 4/5 बराबर-बराबर थे।
उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2025 से 2028 मे आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5 मूल सिंह उम्मेद सिंह
जयसिंह पुत्र जोध सिंह हिस्सा 3/5 व नारायण सिंह सुमेर सिंह किशोर सिंह शिव सिंह पुत्र किशन सिंह
हिस्सा 1/5 उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2028 से 2033 व सम्वत् 2033 से 2036 तक भी इन्ही खातेदारों के नाम
दर्ज चली आ रही थी, परन्तु आधार वर्ष सम्वत् 2044 मे खसरा नम्बर 1644 के नये खसरा नम्बर 5192/3361
नये बना कर उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करके गैर मुमकीन नदी दर्ज कर दी।

वाद-पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज पुराना खसरा नम्बर 1644 रकबा 5 बिघा 6 बिस्वा जो इसके नये
खसरा नम्बर 5162/3361 और इसके नये खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर बने है, इसमें से वादी का
1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 02 का 1/12-1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 4 का
1/8-1/8 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 06 लगायत... 1/40-140
हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 10 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 11 का हिस्सा 1/4 मे
से 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा है, जो कि अपने हिस्से
के अनुसार काबिज एवं काश्त है। भू-प्रबन्ध द्वारा वादग्रस्त भूमि जो वादी व प्रतिवादीगण की खातेदार व काश्त
की भूमि को बिना अधिकार व बिना किसी कानून के भू-प्रबन्ध द्वारा (सैटलमेंट) कृषि भूमि की खातेदारी को
गैरमुमकीन नदी दर्ज कर दी, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं था। उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर बिना
अधिकार के वादी की व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत बनाया गया जो वादी व
प्रतिवादीगण के अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण से बेअसर व शून्य है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से किसी
को कोई अधिकार पैदा नहीं होता है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड से किसी को कोई अधिकार पैदा नहीं होता है,
परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के कारण वादी व प्रतिवादीगण प्रतिवादी नम्बर 14 बेदखल करने पर आमादा है,
अगर गलत रूप से बदेखल कर देंगे तो वादी व प्रतिवादीगण को सख्त तल्फ होगी। ऐसा करने का कोई
कानूनी अधिकार नहीं है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-के तहत भू-प्रबन्ध बिना किसी सक्षम न्यायालय की
डिक्री व आदेश के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड
बनने के कारण वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ वाद घोषणार्थ व दुरुस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद
पेश किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 14 की नियत में फर्क आ गया गलत व राजस्व रिकार्ड की आड में वादी व
प्रतिवादीगण को किसी भी क्षण उसके वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अगर प्रतिवादी नम्बर 14
अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को अपने वैधिक अधिकारों से वंचित होने
पड़ेगा। जिसकी वजह से व्यर्थ की मुकदमे बाजी मे फसना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान इतना होगा जिसकी क्षति

ए. सी. ई. ए. (नं. ३)
नवलगाव

किन्ती भी रूप में सम्भव नहीं होगी तथा मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी पड़ेगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी व काश्त की भूमि में न तो स्वयं बेदखल करने की कार्यवाही करे तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से ऐसा कार्य करवावे। और ना ही किसी कार्यवाही स्वयं करे। जिससे वादी व प्रतिवादीगण को अपने हक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा और नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी। प्रतिवादी नम्बर 14 कब्जे काश्त में ना स्वयं दखलन्दाजी करे और ना ही अन्य किसी से करवावे। शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग लाट-बांट करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 14 गलत राजस्व रिकार्ड की आड में वादी व प्रतिवादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी व काश्त की कृषि भूमि को गैर मुमकीन नदी नाला मानकार बिना किसी कानून के वादी व प्रतिवादीगण को हटाने में आमादा है, तथा कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने में आमादा है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है प्रतिवादी नम्बर 14 ने ऐलानिया रूप से धमकी दी है कि काश्त नहीं करने दूंगा व काश्त करोगे तो फसल को कुर्क करूंगा व कब्जे राज ले लूंगा। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

उक्त वादी के लिए वाद कारण दिनांक 08.10.2015 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने व प्रतिवादी नम्बर 14 द्वारा वादी को धमकी देने के रोज वादकारण राज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। और हर काश्तकार को अपने कब्जे काश्त की भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का वादाधिकार हमेशा ही पैदा रहता है।

प्रतिवादी नम्बर 14 लोक सेवक के विरुद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक होता है, लेकिन मामला अति-अर्जेन्ट नेचर का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी का पेश कर न्यायालय की अनुमति से प्रतिवादी नम्बर 14 को पक्षकार बनाकर यह दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, तथा ग्राम परसरामपुरा में स्थित है, एवं पक्षकारान वाद भी अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं।

वादी द्वारा वाद-पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य की घोषणा की डिक्ली फरमाया जाकर वाके ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1644 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जो इसके नये खसरा नम्बर 5162/3361 और इसके नये खसरा नम्बर 272 रकबा 0.90 हैक्टर बने है इसमें से वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 का 1/12-1/12, प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 का 1/8-1/8, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 7 का 1/40-1/40, प्रतिवादी नम्बर 08 लगायत 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 11 का हिस्सा 1/4 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 13 का प्रत्येक को 1/8-1/8 है। हिस्सेनुसार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रतिवादी नम्बर 14 तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। वादी व प्रतिवादीगण के काश्त व कब्जे की भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत राजस्व रिकार्ड से खातेदारी समाप्त कर गैर मुमकीन नदी दर्ज की गई की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम की घोषणा करने का आदेश फरमाया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

प्रतिवादी नम्बर 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि को ना तो स्वयं बेदखल करने की कार्यवाही करे ना ही आने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवावे ना ही लाट-बांट की बाधा उत्पन्न करे ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवावे। उपयोग-उपभोग का कार्य शांतिपूर्वक करने देवे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो व वादीगण के हक में पडती हो वह भी दिलवाई जावे। मुकदमा हर्जा-खर्चा दिलवाया जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह शेखावत ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा वादी द्वारा जो वाद-पत्र पेश किया गया है उसको दिनांक 05.04.2022 को स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किये जाने की सहमति प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 14 की ओर बावजूद

ए. सी. ई. एम. (न. दे.)
नवलगढ

न्यायालय की एस.एल.पी.(सी.) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में
निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या
1506/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार
निर्णयित किया है कि नदी, तालाब, जोहड़ पायतन जो धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों के संबंध में प्रतिबंधित
भूमि की है। अतः इनमें खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। ना ही किसी प्रकार की स्थाई
निर्णय जारी की जा सकती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के
आधार पर साबित करने में असफल रहा है। वादी के पक्ष में किसी प्रकार की घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का
आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में वाद वादी स्वीकार किए जाने
योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिफ्री
पत्रक से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल
कराए जायें। निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. देवयानी (अ.दे.)
सहायक कलक्टर (फ़ास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०- 236/2015 (विजय सिंह आदि बनाम अजय सिंह आदि)

पर्चा-डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुकदमालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.07.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2022 को जारी की गई।


ए.सी.ई.एम. (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मोहर